अगस्त, 2007 माह के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में मंत्रिपरिषद , विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों आदि के बीच परिचालनार्थ महत्वपूर्ण मामलों का मासिक सार

***

अगस्त, 2007 माह के दौरान शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों/मामलों का मासिक सार इस प्रकार है :-

1. **सार्वजनिक महत्व के मामले**

(i) के0लो0नि0वि0 से संबंधित निम्नलिखित दो समारोह विशेष रुप से उल्लेखनीय हैं:-

(क) राष्ट्रपति संपदा के ऑडिटोरियम व बैंकट हाल 2100.99 लाख रुपये की लागत से कार्य पूरा हुआ और भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इसका उद्‌घाटन किया ।

(ख) श्री विजयेन्द्र नाथ कौल , भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एजी कालोनी, युसुफगुडा, हैदराबाद में 152 स्टाफ क्वार्टरों (टाइप-II के 48, टाइप-III के 88, टाइप-iV के 16) के निर्माण कार्य का दिनांक 16 अगस्त, 2007 को उद्‌घाटन किया । इस परियोजना की लागत 749.50 लाख रुपये थी ।

2. **नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामले**

(ii) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत आरंभ की गई साझा वित्त विकास कोष स्कीम(पीएफडीएफ)

अभी तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, तथा असम राज्यों ने स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए अपनी ''राज्य साझा वित्त संस्था'' की स्थापना की है । गोवा राज्य ने यह सूचित किया है कि राज्य में एक राज्य साझा वित्त संस्था की स्थापना करना संभव नहीं है । तमिलनाडु शहरी विकास कोष चेन्नई से प्राप्त 45 करोड़ रुपये मूल्य के कर मुक्त साझा वित्त विकास बांड जारी करने के प्रस्ताव की इस मंत्रालय में जांच की जा रही है ।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधि(विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 दिनांक 4.7.2007 को प्राख्यापित अध्यादेश के प्रतिस्थापन के लिए दिनांक 20.8.2007 को लोक सभा में पेश किया गया है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुछेक श्रेणियों के अनधिकृत विकास को बलपूर्वक कार्रवाई से अस्थाई राहत दिलाने के लिए 19.5.2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू मान लिया गया है ।

(iv) सरकारी मुद्रणालयों , प्रकाश विभाग तथा लेखन सामग्री कार्यालय के कार्यों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 27.8.2007 को अधोहस्ताक्षरी ने एक बैठक

आयोजित की थी । इन सरकारी इकाइयों की कार्यप्रणाली में समयबद्ध ढंग से तेजी लाने के लिए कई निर्णय लिए गए जैसे- सरकारी मुद्रणालयों , नासिक तथा कोयम्बटूर में वाणिज्यिक लेखांकन प्रणाली लाना, भारत सरकार मुद्रणालयों में अपनाए जा रहे लागत व कीमत निर्धारण प्रणाली में संशोधन करना, भारत सरकार मुद्रणालयों के पास उपलब्ध अधिशेष भूमि के उपयोग की संभावना की जांच करने के लिए सीसीए की अध्यक्षता में समिति गठित करना, भारत सरकार मुद्रणालयों के प्रबंधकों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि करने, कार्यकुशलता की नियमित जानकारी प्राप्त करने, बकाया मुद्रण प्रभारों की भी इस वसूली की मानीटरिंग के लिए संयुक्त सचिव(यूडी)की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन करना इत्यादि ।

(v) इस मंत्रालय ने विश्व बैंक/जीईएफ से सहायता प्राप्त स्थायी शहरी परिवहन परियोजना के अंतर्गत शहरी परिवहन में क्षमता निर्माण में परामर्शी सेवा के लिए मैसर्स ली एसोसिएट्स साउथ एशिया प्रा0 लि0 को संविदा प्रदान किए जाने को अंतिम रुप दिया है ।

(vi) रेलवे अधिकारियों को बंगलूर मैट्रो रेल कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यभार मुक्त करने के लिए रेलवे मंत्रालय पर दबाव डालने के लिए मेरी अध्यक्षता में दिनांक 14 अगस्त, 2007 तथा 31 अगस्त, 2007 को दो बैठकें आयोजित की गईं । एक ऐसी प्रणाली लाने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई है , जिसमें युवा पेशवर रेलवे संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें ।

(vii) योजना आयोग के सलाहकार ने शहरी परिवहन क्षेत्र के लिए मॉडल कंशेसन एग्रीमेंट (एमसीए) पर 27 अगस्त, 2007 तथा 30 अगस्त, 2007 को बैठकें की ।

(viii) दिल्ली मैट्रो (ओएण्डएम), अधिनियम 2002 के अंतर्गत बनाए गए दावा आयुक्त नियमों को लोक सभा के पटल पर रखा गया ।

(ix) शहरी परिवहन विषय पर चर्चा के लिए 2 अगस्त, 2007 को शहरी विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सम्मुख उपस्थित हुए , जिसकी वर्तमान में समिति द्वारा जांच की जा रही है ।

(x) कोलकाता शहर के लिए 13 अगस्त, 2007 को व्यापक मोबिलिटि प्लान का मूल्यांकन किया गया तथा कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण को शहरी विकास मंत्रालय की टिप्पणी के अनुसार इसमें संशोधन करने का अनुरोध किया गया ।

(xi) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत प्रमुख कार्य :

(क) सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय स्वीकृति और मानीटरिंग समिति की दिनांक 3 अगस्त, 2007 तथा 17 अगस्त, 2007 को बैठकें आयोजित की गई ।

(ख) सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए सभी शहरी स्थानीय निकायों को सामुदायिक भागीदारी कोष(सीपीएफ) की टूलकिट परिचालित की गई ।

(ग) जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत क्षमता निर्माण प्रयास पहल के रुप में सभी शहरी स्थानीय निकायों को कार्यान्वयन इकाइ(पीआईयू) के लिए टूलकिट परिचालित की गई ।

(घ) सीडीपी/डीपीआर तैयार करने की लागत की प्रतिपूर्ति के लिए शहरी स्थानीय निकायों/ एसएलएनए को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से टूलकिट तैयार करके सभी शहरी स्थानीय निकायों को परिचालित की गई ।

(ड.) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत शहरी विकास योजनाओं , करार ज्ञापन(एमओए) तथा केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) के संबंध में प्रगति रिपोर्ट के ब्यौरे अनुलग्नक-। में दिए गए हैं ।

(xii) नेताजी नगर के पुनर्विकास की परियोजना के अंतर्गत प्रगति(नई दिल्ली में सरकारी आवास योजना)

(क) चूंकि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण भूमि के एक हिस्से के अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया अतः यह निर्णय लिया गया था कि भूमि तथा विकास कार्यालय उसे भूमि का पुनः स्वामित्वाधिकार प्राप्त करे और पूरी भूमि का कब्जा एनबीसीसी को सौंपा जाए ताकि वह 7.5 एकड़ भूमि को छोड़कर , जो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की देखरेख , नियंत्रण व अनुरक्षण में कार्यात्मक प्रयोजनार्थ रहेगी, शेष भू क्षेत्र कारेडियो सिगनल टावरों का समुचित पुनर्स्थापन/समेकन करके परियोजना हेतु इसका उपयोग कर सके ।

(ख) एनबीसीसी सहमत समय सीमा के भीतर 500 ईडब्ल्यूएस मकान बनाने पर सहमत हो गया है । तथापि, पुनर्स्थापन/पुनर्वास की पात्रता का निर्धारण एमसीडी द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के नवम्बर, 2006 के आदेश में उल्लिखित इस मंत्रालय द्वारा रखे गए पक्ष के अनुसार किया जानी है ।

(ग) दिल्ली नगर कला आयोग ने एनडीएमसी को संशोधित ड्राइंग भेज दी है ।

(घ) सीई(सीएसक्यू) केलोनिवि ने अप्रैल, 2007 में नये लागत सूचकांक के आधार पर लागत अनुमानों का पुनर्निर्धारण किया है जिन्हें तैयार किए जा रहे व्यय वित्त समिति के नोट में शामिल कर लिया गया है ।

(ड.) वित्त प्रभाग ने समग्र परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत से सम्बन्धित मामले को व्यय वित्त समिति के समक्ष रखने की इच्छा व्यक्त की है । व्यय वित्त समिति ज्ञापन का प्रारुप तैयार किया जा रहा है ।

(XIII) मुम्बई में वर्ष 2007-08 के लिए बृहन मुम्बई वर्षा जल निकास परियोजना के विकास के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा 400 करोड़ रु0 (12.7.2007 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित परियोजना लागत 1200.53 करोड़ रुपये) जारी किए गए । प्रधानमंत्री जी ने उक्त राशि का चैक अपनी मुम्बई यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में प्रदान किया ।

(XIV) दिल्ली में अगस्त,2007 के अन्त तक आवंटित/ पेशकश किए गए /खाली सरकारी आवासों की संख्या तथा संपदा निदेशालय के पास लंबित बेदखली के मामलों की संख्या अनुलग्नक-।। में दी गई है ।

(XV) अगस्त,2007 में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ की परियोजना/ स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान के अन्तर्गत मंजूर/ जारी की गई धनराशि के ब्यौरे अनुलग्नक-।।। में दिए गए हैं ।

(XVI) अगस्त,2007 के दौरान एनबीसीसी को तथा बोस संस्थान , दार्जिलिंग के आडिटोरियम और अतिथि गृह का कार्य 230 लाख रु0 की लागत पर सौंपा गया था ।

(एम0 राजामणि)
संयुक्त सचिव,भारत सरकार

अनुलग्नक-I

अगस्त,2007 के दौरान जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन(जेएनएनयूआरएम) के तहत प्रगति

मद	जून,2007 तक स्थिति	जुलाई,2007 तक स्थिति	अगस्त,2007 तक स्थिति	अद्यतन स्थिति
नगर विकास योजना(सीडीपी)				
i प्राप्त	63	-	-	जेएनएनयूआरएम के तहत सभी 63 शहरों के लिए मूल्यांकित सीडीपी
ii मूल्यांकित	63	-	-	
करार ज्ञापन(एमओए)				
(i) हस्ताक्षरित	56	57	-	57
केन्द्रीय संस्वीकृत और निगरानी समिति की बैठके				
आयोजित बैठकों की संख्या	33*	34*	2	36*
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	216	230	12	242
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए (183 परियोजनाओं के लिए)	1641.52 करोड़ रुपए	1763.97करोड़ रुपए	475.58करोड़ रुपए	2239.55करोड़ रुपए

- दो विशेष सीएसएमसी बैठको को मिलाकर,जो कि 04.06.07 और 13.06.07 को आयोजित की गई ।

अनुलग्नक-II

अगस्त, 2007 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित / पेशकश किए गए / खाली कराए गए सरकारी मकानों /क्वार्टरों की संख्या और लंबित बेदखली मामलों की संख्या

****

टाईप	आवंटित/ पेशकश किए गए मकानों की संख्या	स्वीकार किए गए मकानों की संख्या	मकानों की संख्या जिन्हें नामंजूर करने के कारण आगे ले जाया गया	रद्द किए गए क्वार्टरों की संख्या जिनमें इस माह के दौरान बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है	ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या जिनके संबंध में बेदखली कार्रवाई चल रही है
टाईप-I	243	97	93*	45	44
टाईप-II	468	127	341	24	162
टाईप-III	441	107	334	40	75
टाईप- iv	180	92	88	07	25
टाईप- iv (स्पेशल)	27	15	12	1	8
टाईप- V क (डी-II)	55	20	35	2	25
डी-I	61	7	54	--	2
सी-II	22	9	13	--	3
सी-I व उससे ऊपर	11	6	5	--	10
हॉस्टल	57	6	51	2	4

* 53 क्वार्टरों के लिए अभी भी आवंटियों से स्वीकृति/अस्वीकृति प्रतीक्षित है ।

अनुलग्नक-III

अगस्त,2007 माह के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के सम्बन्ध में परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	दी गई राशि
1	हवाई,अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थलों का विकास (पूर्व - एजेंसी- राज्य सरकार)	40.76
2	हवाई, अरुणाचल प्रदेश में गैस्ट हाऊस का निर्माण (पूर्व - एजेंसी- राज्य सरकार)	44.10
3	बोमडिला(फेज-I),अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग एवं शापिंग काम्पलैक्स का निर्माण , (पूर्व - एजेंसी- राज्य सरकार)	97.80